ISSN 2395-051X

भारत में नोटों का विमुद्रीकरण कारण एवं प्रभाव

डॉ. एम.एम. चौकसे
प्राध्यापक - वाणिज्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 8 नवम्बर 2016 को रात आठ बजे दूरदर्शन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 एवं 1000 रूपये के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की गई। इस घोषणा में 8 नवम्बर की आधी रात से 500 एवं 1000 रूपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कालेधन पर नियंत्रण, जाली नोटों से छुटकारा, आतंकवादी तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाना है। तथा नगद रहित समाज की स्थापना तथा डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देना है।

इससे पहले भी 1946 में 1000 एवं 10000 के नोटों को वापिस लिया गया था, और 1000, 5000 और 10000 रूपये के नये नोट 1954 में पुनः शुरू किये गये थे। 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने फिर से 1000, 500 एवं 10000 रू. के नोटों का विमुद्रीकरण किया था, ताकि जालसाजी एवं काले धन पर अंकुश लगाया जा सके।

28 अक्टूबर 2016 को भारत में 17.77 लाख करोड़ की मुद्रा चलन में थी। मूल्य के आधार पर 31 मार्च 2016 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार चलन में नोटों की कुल कीमत 16.42 लाख करोड़ है। जिसमें से 86 प्रतिशत अर्थात् 14.18 लाख करोड़ 500 और 1000 के नोट थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी अधिकारिक घोषणा के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटैल और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट किया कि सभी वर्गो की नोटो की आपूर्ति में 2011 एवं 2016 के बीच में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 500 एवं 1000 के नोटों में इस अवधि में क्रमशः 76 प्रतिशत एवं 109 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 500 एवं 1000 रूपये के नोटों का उपयोग, कालेधन, जालीमुद्रा के रूप में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के कारण सरकार ने इन नोटों को बंद करने का निर्णय लिया। तालिका क्र. 1 में देश में मार्च 2014 से मार्च 2016 के बीच 500 एवं 1000 रूपये नोटों की मात्रा तथा कीमत को दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 1

500 एवं 1000 नोटों के चलन की मात्रा एवं कीमत

विवरण मात्रा करोड़ नोटों की मूल्य लाख रूपये में

	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16
500 रू. के नोट	1141	1313	1571	5.7	6.6	7.9
अंश प्रतिशत में	14.7	15.7	17.4	44.4	45.9	47.8
1000 के नोट	508	561	633	5.1	5.6	6.3
अंश प्रतिशत में	6.6	6.7	7.0	39.6	39.3	38.5
500 एवं 1000 के नोट संयुक्त	1949	1874	2203	10.8	12.2	14.2
अंश प्रतिशत में	21.3	22.4	24.4	84.1	85.2	86.4
कुल नोट	7733	8358	9027	12.8	14.3	16.4

स्त्रेत रिजर्व बैंक आफ इंडिया

8 नवम्बर 2016 के बंद किये गये नोटों को बदलने की प्रक्रिया बैंक तथा पोस्ट आफिस के माध्यम से 30 दिसम्बर 2016 तक जारी रही इसके पश्चात् मार्च 2017 तक नोटों को बदलने का कार्य रिजर्व बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पूरा किया जायेगा।

नोट बंदी के सकारात्मक प्रभाव

1. **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव** - 500 एवं 1000 के नोटों पर पाबंदी के बाद करेंसी अर्थव्यव्था की कमियों (कालेधन, नकदी नोट और छद्य बैंकिंग) आदि को भरेंगे। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों में विकास दर बांग्लादेश में 6.55 फीसदी, पाकिस्तान में 5.54 फीसदी, श्रीलंका में 4.79 फीसदी नेपाल में 3.36 फीसदी अफगानिस्तान में 1.52 फीसदी है। यही दर भारत में लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

2. **राजनीति एवं चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होगी** - यह सर्वविदित तथ्य है कि राजनैतिक दल कालेधन का उपयोग बड़ी मात्र में चुनाव के दौरान करते हैं अभी हाल में देश के पॉच राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर तथा उत्तर प्रदेश में चुनाव में बड़ी मात्र में नई व पुरानी मुद्रा का बरामद होना इसका प्रमाण हैं, इन राज्यों में ब्लैकमनी का उपयोग नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के खाते में नोट बंदी के दौरान 112 करोड़ रूपये जमा हुए।

3. **सस्ते होंगे मकान** - रियल स्टेट सेक्टर में 6.5 लाख करोड़ रूपये 2014 में लगे थे। जो देश की जी.डी. पी. का 11 प्रतिशत था तथा कुल नगद लेनदेन का 30 प्रतिशत था। इस सेक्टर में बड़े नोटों के बंद होने से कालाधन का उपयोग नहीं होगा। नोट बंदी के अनुमान किया जा रहा है कि बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में कमी की है। इससे फ्लेट की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत तक गिरावट का अनुमान किया जा रहा है देश की सबसे

ज्यादा ब्लैक मनी इसी सेक्टर में खपाई जाती है। फ्लैट की कीमतें कम होने से अपने घर का सपना देखने वालों के सपने पूरे होगें।

4. **कालेधन पर प्रभाव** - 2014 में आम चुनाव में तथा सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कालाधन समाप्त करने हेतु कड़े प्रावधान लागू करने तथा अपने सहयोगी देशों से ब्लैक मनी खत्म करने के समझौते करने का वादा किया है। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कड़े प्रावधान भी किये हैं नोट बंदी लागू होने के बाद 500 एवं 1000 रू. के नोटों को जलाने, कूड़ेदान में फेंकने तथा नदियों में बहाने के समाचार प्राप्त हुये 29 नवम्बर 2016 तक आयकर विभाग द्वारा 678 जगह पर छापा मारकर 3600 करोड़ रू. का कालाधन जप्त किया।

5. **नकली नोट बंद होंगे** - सरकार द्वारा 500 एवं 2000 रूपये के नये नोट जो नोट बंदी के बाद जारी किये गये है उनमें अनेको ऐसे सुरक्षा फीचर जोड़े गये हैं जिनकी नकल करना आसान नहीं होगा। अतः पाकिस्तान जैसे देश जो नकली नोट देश में भेजते थे अब आतंकी गतिविधियों को जारी नहीं रख जायेगे।

6. **इस्लामिक आतंकवाद से छुटकारा** - 500 एवं 1000 रूपये के नोट बंद होने के कारण जम्मू कश्मीर सहित देश के जिन इस्लामिक संगठनों ने अपने पास बड़ी मात्र में इन रूपयों के रूप में जो धन जमा किया था वह अब बेकार हो गया। पाक से नेपाल, बांग्लादेश के माध्यम से जो रकम इन नोटों की शक्ल में भारत आती थी अब वह बंद होगी. नोट बंदी के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी, तथा आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगी है।

7. **शेड़ो बैंकिंग** - शैडो बैंकिग का मतलब है बैंक जैसी गतिविधियॉ करना। इन पर बैंकिंग जैसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती और न ही कानूनी शिकंजा, बैंकिग सिस्टम से बाहर यह लोग वित्तीय लेन देन करते है. 500 एवं 1000 के नोट बंद होने से शैडो बैंकिंग बंद होगी।

8. **आम जनता की मासिक किश्त कम होगी** - नोट बंदी के बाद बैंकों के पास जिस तरीके से धन की वापिसी हुई उससे बैंकों में नकद जमा राशि में वृद्धि हुई है। नोट बंदी में 29.12.16 तक 14 लाख करोड़ रूपये के नोट वापिस आ चुके थे यानि प्रचलित मुद्रा का लगभग 91 प्रतिशत राशि बैंकों के पास जमा धन वापिसी से उनके पास नगद राशि की मात्र बड़ी है अतः बैंक सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने की स्थिति में है बैंक लोगों को कम दर पर ऋण देगें फलस्वरूप लोगों को मासिक किश्त कम भरनी पड़ेगी।

नोट वंदी के नकारात्मक प्रभाव

1. **कृषि क्षेत्र पर** - इस क्षेत्र में देश की 49 प्रतिशत आबादी रोजगार रत है जहॉ 97 प्रतिशत रोजगार की प्रकृति अनौपचारिक है। रबी फसल के सीजन की शुरूआत में नोट बंदी से किसानों को भारी दिक्कतों का सामाना करना पड़ा किसानों को हफ्तों बीज तथा खाद क्रय करने के लिये नकदी न मिल पाने के कारण इंतजार करना पड़ा वहीं खरीफ की फसल की नगद बिक्री न मिल पाने के कारण किसानों को भारी कठिनाई झेलनी पड़ी।

2. **कुटीर एवं लघु इकाईयॉ** - देश की लगभग 60 प्रतिशत लघु इकाईयॉ ग्रामीण क्षेत्रों में है यह इकाईयॉ नगद राशि न मिलने का दंश झेल रही हैं देश के कुछ क्षेत्रों में आई अप्रत्याशित बाढ़ ने इन इकाईयों के उत्पादन को प्रभावित किया तथा इन इकाइयों की बिक्री घटने से इन इकाइयों द्वारा लिये गये कर्ज को चुकाने का संकट पैदा हो गया है।

3. **परिवहन** - नोट बंदी के शुरूआत दौर में पेट्रोल तथा डीजल भरवाने के लिये पुराने नोटों में भुगतान की सुविधा दी गई थी. लेकिन रास्ते के खर्चों ड्राइवरों के वेतन व मरम्मत की राशि न मिलने के कारण परिवहन व्यापार पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा देश में कारों की बिक्री में 70-71 फीसदी की कमी की अशंका दिखाई गई दोपाहिया वाहनों की बिक्री पर असर पड़ा।

4. **सीमेन्ट तथा स्टील उद्योग पर प्रभाव** - स्टील क्षेत्र पर नोटबंदी प्रभाव पड़ा क्योंकि छोटी मिले और रोलर कारखाने अधिकतर कारोबार नगद में करते हैं इनमें से कुछ इकाइयां बंद हुई हैं दिसम्बर 2016 के अंत तक सीमेन्ट की मॉग में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी आई है मॉग में कमी का मुख्य कारण निर्माण कार्यों का बंद होना है भवन निर्माण में मजदूरी का भुगतान अधिकतर नकद करना होता था सरकार द्वारा नकदी पर प्रतिबंध लगाने तथा बैंकों से नकद निकासी पर बार-बार नियमें में किये जाने कारण भवन निर्माता मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं कर पाये।

5. **मोबाइल फोन की बिक्री पर प्रभाव** - नोट बंदी के पहले देश में प्रतिदिन लगभग 400 करोड़ रूपये के मोबाइल फोनों की बिक्री होती थी। वह नोट बंदी के बाद घटकर प्रतिदिन 200 करोड़ रूपये की रह गई. मेक इन इंडिया अभियान की शुरूआत की बाद से पिछले 18 महीने में 40 छोटी बड़ी कम्पनियॉ देश में मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन की तैयारी कर रही थी. लेकिन अब उन्होने अपने कदम फिलहाल रोक लिये इससे नौकरियों पर बड़े पैमाने पर असर पड़ने वाला है।

6. **आम जनजीवन पर प्रभाव** - नोट बंदी के बाद सरकान ने रोजाना एटीएम से रकम निकालने की सीमा 2000 तय की, लेकिन देश में मौजूद लगभग 2 लाख एटीएम में नकदी नहीं थी। सरकार द्वारा जारी 2000 तथा 500 के नये नोट तकनीकि दिक्क्त के कारण नहीं निकाल पा रहे थे। बैकों तथा एटीएम के बाहर भारी मात्रा में भीड़ जमा होने लगी. प्रशासन को व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस व्यवस्था करनी पड़ी पूरा देश कतारों में नजर आने लगा। लोग अपना व्यवसाय तथा अन्य कार्यो को छोड़कर एटीएम से पैसा निकालने या 4500 रू. बदलने के लिये बैंकों के चक्कर लगाने को मजबूर हो गये। जरूरत मंदों को दवाईयां समय पर नहीं मिली लोगों के रूपये बैंक में जमा होने के वावजूद भी राशि न मिलने के कारण चिकित्सा सुविधायें नहीं मिली। चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण लोगों की मौत भी हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में जहॉ बैंक या एटीएम नहीं थे वहॉ के ग्रामीणों को अपने गॉवों से 15 से 20 कि.मी. तक जाकर नोट बदलवाने के लिये या पैसा निकालने के लिये अपना समय व धन बरबाद करना पड़ा। नोट बंदी के समय जो लोग सफर में थे उनके पास 500 या 1000 रूपये के नोट थे, नोट बंदी के कारण अगली सुबह रास्ते में चाय नाश्ता भी नसीब नहीं हुआ कुछ खबरें तो ऐसी भी आई की बच्चों को रूपये के अभाव रास्ते में दूध तथा बिस्कुट मिलना भी नसीब नहीं हुआ। जिन परिवारों में शदियॉ थी उनको भी नोट बंदी के असर के दंश को झेलना पड़ा, लोगों के पैसे बैंकों में जमा होने के बावजूद व पैसा न निकाल सके इस कारण से कुछ शादियॉ टूटी, कुछ शादियॉ तय समय पर नहीं हो सकी और कुछ जगह लड़कियों द्वारा आत्महत्या किये जाने की भी खबरे आई सरकार ने शादियों के लिये भी 2.50 लाख की अधिकतम सीमा तय की थी, उसमें भी अनेक कानूनी अड़चन थी कुछ बुजुर्गों, महिलाओं तथा असहाय लोगों को भीड़ में इंतजार करते समय मृत्यु के समाचार मिले, नोट बंदी का जनजीवन पर खासकर ग्रामीण तथा गरीब लोगों पर सवसे वुरा असर पड़ा दैनिक मजदूर, कारीगर, तथा प्रतिदिन मजदूरी पाने नकद राशि न मिल पाने के

कारण सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, सरकारी सेवाओं पर इसका बुरा असर रहेगा, लोग समय पर टैक्स, अपनी मासिक किश्ते अदा नहीं कर पाये।

अन्य प्रभाव -

1. **बैंक माफिया** - नोट बंदी के बाद कई ऐसे लोग सामने आये जिन्होनें 15 से 80 फीसदी रकम लेकर पुरानी करेंसी के बदले नई मुद्रा प्रदान की इनमें सकारी बैंक निजी बैंकों के कर्मचारियों तथा अधिकारी शामिल थे।

2. **स्वर्ण आभूषणों पर विनियोग** - नोट बंदी के 4 दिनों के भीतर देश के लगभग 25 टन सोने के आभूषण लोगों ने खरीदे जिनका अनुमानित मूल्य 7750 करोड़ था, नोट बंदी की रात्रि में 8 बजे से 12 बजे रात्रि के बीच स्वर्ण आभूषण के रेट 30 हजार प्रति 10 ग्राम की जगह 50000 प्रति 10 ग्राम हो गये।

3. **रेल टिकिट** - दलालों ने बड़ी मात्रा में अग्रिम तारीखों में रेल टिकिट राजधानी एक्सप्रेसों में तथा अन्य सुपर फास्ट ट्रेनों ए.सी., प्रथम श्रेणी के पुरानी मुद्रा में बुक कराये क्योंकि रद्द कराने में उन्हें भुगतान नयी मुद्रा में मिलना था।

4. **अमीर गरीब भाई-भाई** - नोट बंदी के बाद अमीरों ने गरीबों के जनधन खातों में सरकार द्वारा तय सीमा 2.5 लाख रूपये के नोट जमा कराये कुछ कमीशन के बदलों में जिससे बाद में वापिस ले लिया जायेगा।

5. **धर्मादा खाता** - मुम्बई के सिद्धि विनायक मंदिर, बालाजी तिरूपति मंदिर, साई बाबा मंदिर, नासिक के त्रिम्बेकेश्वर मंदिर में चंदों की वाढ़ आ गई। मंदिरों में चढ़ावे तथा हुण्डियों की कोई जॉच नहीं होती, मंदिरों के महंतों तथा पुजारियों द्वारा कमीशन लेकर बड़ी मात्रा में कालेधन को बदला।

6. **पेट्रोल पम्प मालिकों ने कमाये** - नोट बंदी के बाद डीजल तथा पेट्रोल भरवाने पर पुराने नोटों के भुगतान की सुविधा दी गई थी। इस सुविधा का लाभ लेकर पेट्रोल पंप संचालकों ने करोड़ो के पुराने नोटों को नये नोटों में बदलवाकर लाखों रूपये कमाये।

7. **जमीन की बिक्री** - जमीन मालिकों ने फर्जी तरीके से 8 नवम्बर के पहले की तारीख की बिक्री दिखाकर पुराने नोटों को बैंकों में जमा कर दिया तथा बाद में भुगतान नई मुद्रा में प्राप्त किया।

8. **सरकारी कर्मचारियों द्वारा हेरफेर** - सरकार ने बिजली विभाग, नगर निगम, रेल्वे तथा सरकारी विभागों में बकाया राशि नवम्बर माह में पुरानी मुद्रा में जमा करने की सुविधा प्रदान की थी, इन विभागों के कर्मचारियों ने पुरानी मुद्रा को गलत तरीके से लेकर कमीशन के बदले में बैंक में जमा कराया।

9. **अग्रिम किराया** - लोगों ने मंहगे इलाकों में स्थित फ्लेंट तथा मकान किराये पर लेकर तीन साल तक का किराया अग्रिम भुगतान के रूप में पुराने नोटों में किया।

सरकार द्वारा घोषित नोट बंदी का मुख्य उद्धेश्य नगद रहित अर्थ व्यवस्था तैयार करना था. नगद रहित लेन देन में पारदर्शिता रहेगी जिससे सभी प्रकार के लेन देन का पता लगाया जा सकता और उस पर नजर रखी जा सकती है इससे आतंकवाद नक्सलवाद तथा अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिये दी जा रही राशि का पता लगाने में सरकार को मदद मिलेगी, लोगों के पास मौजूद धन बैंक में जमा रहेगा, जिससे यह राशि वापिस अर्थव्यवस्था में आयेगी और जरूरतमंद को ऋण दिया जा सकेगा।

भारत में आज भी 90 प्रतिशत लेन देन नगद रूप में होते है। यहॉ आज भी निरक्षर तथा कम पढ़े

लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी एटीएम (स्वैप मशीन अगस्त 16 तक 14 लाख 62 मशीन थी) इंटरनेट की सुविधाओं का अभाव, नैट बैंकिंग की कमी, स्मार्ट मोबाईल फोन के कम उपयोग कर्त्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खाते न होना बिजली का न होना, साइबर अपराध जैसी अनेक कमियाँ हैं जो नकद रहित लेन देन की रास्ता में बाधक तत्व है, सरकार इन कमियों को दूर करने हेतु सतत् कार्य कर रही है।

भारत में अगस्त 2016 तक 71.25 करोड़ डेबिट कार्ड तथा 2.64 करोड़ क्रेडिट कार्ड हैं इनमें से 85 प्रतिशत से अधिक लोग केवल पैसे निकालने के लिये कार्ड का उपयोग करते हैं। कार्ड से भुगतान करने पर शुल्क अलग से देना होता इस कारण लोग इसके प्रयोग करने से बचते हैं।

नोट बंदी के तत्कालिक प्रभाव भले ही नकारात्मक या कम प्रभावशाली लगे, लेकिन सरकारी प्रयास तथा आम जनता के सहयोग से आने वाले समय में इसके न केवल कालेधन, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, नकदी लेन देन पर रोक लग सकेगी अपितु यह देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में सकारात्मक दिशा दे सकेगी। यह आशा की जानी चाहिये।

सन्दर्भ

1. मुक्त ज्ञान कोष विकिपीडिया।
2. रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट।
3. इंडिया टुडे के माह नवम्बर दिसम्बर 2016 के संस्करण।
4. योजना पत्रिका माह फरवरी 2017।
5. दैनिक भास्कर समाचार पत्र नवम्बर दिसम्बर।
6. आज तक न्यूज चैनल।
7. एनडीटीव्ही इंडिया न्यूज चैनल।
8. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'मन की बात' रिप रेडियो वार्ता।